बैंकों द्वारा किसानों से ब्याज की अधिक दर का वसूल किया जाना

118. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि कुछ संसद सदस्यों ने 19 दिसम्बर, 1985 के अपने पत्र ने भूमि विकास बैंक, बिहार तथा कुछ अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के विरुद्ध छोटे और सीमान्त किसानों से ब्याज की अधिक दर वसूल किये जाने तथा उन्हें अनुदानों का समय पर भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में आरोप लागये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) एक संसद सदस्य से दिनांक 19 दिसम्बर 1985 का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें बिहार में कृषि प्रयोजनों के लिये दिए गए अग्रिमों के मामले में भूमि विकास बैंक सहित बैंकिंग प्रणाली के अधिकारियों द्वारा अपनाए गए विभिन्न भ्रष्ट तरीकों का आरोप लगाया गया है । उक्त पत्र में उठाए गए मुददों की ओर पहले भी सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया था और इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा जांच करवाई गई थी । जांच के आधार पर केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने छः बैंक अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की सिफारिश की थी । संबधित बक ने भी छः अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिये अपनी आवश्यक सहमति दे दी थी । इस मामले की विभिन्न एजेंसियों और राज्य सरकार, केन्द्रीय जांच ब्यूरों तथा केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों द्वारा भी जांच की गई है । इन सब जांचों के परिणामस्वरूप निष्कर्षों के आधार पर, बिहार राज्य सरकार को राज्य सरकार के संबंधित दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है ।

पर्यटन संबंधी साहित्य का अभाव

119. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **संसदीय कार्य और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में पर्यटन सम्बन्धी साहित्य की नितान्त कमी है जिसके कारण अपने देश के तथा बाहर के देशों के लोग इस देश के रमणीक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा मनोरजक स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते ;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार रखती है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पर्यटन विभाग ने इस सम्बन्ध एक मासिक पत्रिका प्रकाशित करने का फैसला किया था और इस सम्बन्ध में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं, यदि हां, तो इस बारे में अब क्या स्थिति है ; और

(घ) क्या पर्यटन विभाग राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रयास कर रहा है, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) जी नहीं । सभी प्रमुख पर्यटक केन्द्रों और साथ ही साथ कम प्रसिद्ध स्थानों गन्तव्यों को समाहित करते हुए पर्यटन विभाग के मुद्रण प्रकाशन कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अब तक सौ से ज्यादा शीर्षक मुद्रित किए जा चुके है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) तत्कालीन पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की सिफारिशों के अनुसरण में पर्यटन विभाग एक द्विभाषिक पत्रिका का प्रकाशन करने पर विचार कर रहा है ;